



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)



Website- msuniversity.ac.in

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 79 / 10 / एके० / MSU / 2024-25

दिनांक : 12/11/24

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

02. शैक्षणिक समन्वयक
विश्वविद्यालय परिसर

विषय: भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1219/सत्तर-4-2024-70-4002(001)/2024, दिनांक : 12 नवम्बर, 2024 एवं अनुसचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के पत्र दिनांक : 08 नवम्बर, 2024 के साथ संलग्न सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी०एम०आई०एस०-01/10/2024, दिनांक : 30 अक्टूबर, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हुये इसके सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना का लक्ष्य आगामी 05 वर्षों में 01 करोड़ युवाओं को भारत की 500 कम्पनियों में इंटरनशिप प्रदान करना है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के दिशा-निर्देश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटरनशिप वेबसाइट एवं वीडियो लिंक संलग्न कर प्रेषित है।


संलग्नक - यथोपारं।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
02. अनुसचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ०प्र० शासन।
03. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।


उपकुलसचिव

PM Internship Website

<https://pminternship.mca.gov.in>

प्रशिक्षण LMS Video Link in Hindi

<https://www.youtube.com/watch?v=WrCEpQ6BzNU>

<https://www.youtube.com/watch?v=0VCbbGfEVbA>

<https://www.youtube.com/watch?v=1F6RiNsf1Eg>

प्रशिक्षण LMS Video Link in English

https://www.youtube.com/watch?v=CRUpP_wlVo0

<https://www.youtube.com/watch?v=tWRODZVbhoE>

<https://www.youtube.com/watch?v=v-tFRd1jVxw>

ई-मेल/महत्वपूर्ण
संख्या-1219/सत्तर-4-2024-70-4002(001)/2024

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासना

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 2024

विषय:-भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के पत्र दिनांक 08.11.2024 के साथ संलग्न सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी०एम०आई०एस०-01/10/2024, दिनांक 30.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हुए इसके सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना का लक्ष्य आगामी 05 वर्षों में 01 करोड़ युवाओं को भारत की 500 कम्पनियों में इंटरशिप प्रदान करना है।

2- अतः उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.11.2024 एवं 30.10.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार द्वारा संचालित प्रश्नगत योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों संबंधित सूचनाएं निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा एवं राज्य/निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचनाएं अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा संकलित करते हुए शासन को उपलब्ध कराई जाएंगी।

संलग्नक यथोक्त

Signed by

भवदीय,

Prem Kumar Pandey

Date: 12-11-2024 16:14:20

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

वी0सी0 दिनांक 09.11.2024 अपराह्न 04.00 बजे

प्रेषक,

धर्मपाल पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

No. 10677 VIP/HE/CD/PP/CO/2024

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/
चिकित्सा शिक्षा विभाग/दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग/
समाज कल्याण विभाग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ दिनांक: 08 नवम्बर, 2024

विषय: भारत सरकार की "प्रधानमंत्री इन्टरनशिप योजना" के क्रियान्वयन हेतु विशेष सचिव,
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में
दिनांक 09.11.2024 को अपराह्न 04:00 बजे आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग की बैठक के संबंध

महोदय,
महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शा0 पत्र
संख्या- पी0एम0आई0एस0-01/10/2024 दिनांक 30.10.2024 (प्रति संलग्न) का कृपया
सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो "प्रधानमंत्री इन्टरनशिप योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में
राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किय जाने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार
के उक्त पत्र में प्रश्नगत योजना संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश एवं पात्रता/ शैक्षिक योग्यता का
भी उल्लेख किया है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित की गयी "प्रधानमंत्री इन्टरनशिप
योजना" के सफल क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श किये जाने हेतु श्री अभिषेक सिंह,
उच्च शिक्षा, नागरिक सुरक्षा, विज्ञान सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 शासन की
राजनैतिक पेशन एवं सहकारिता विभाग, विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 शासन की
अध्यक्षता में दिनांक 09.11.2024 को अपराह्न 04.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से
बैठक आहूत की गयी है।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार आहूत वी0सी0 में
शासन स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर/ संबंधित विश्वविद्यालय के भिन्न अधिकारियों को सुसंगत
सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। बैठक हेतु लिंक एवं पासवर्ड
निम्नवत् है:-

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/81370976677?>

pwd=j6dJhXOC25GjDF6jxoRqt5EbOnx4Vn.1

50-4 (H/R)
07/11/2024

50-3

50-3/दिनांक 11/11/24

08/11/24

(आर० पी० चौधरी)

निजी सचिव,

प्रमुख सचिव, योजना

उच्च शिक्षा, नागरिक सुरक्षा,
राजनैतिक पेशन एवं सहकारिता विभाग,

विज्ञान सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 शासन की

अध्यक्षता में दिनांक 09.11.2024 को अपराह्न 04.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से

बैठक आहूत की गयी है।

4411/USC/2024

50-3

3
8-9-11

(रुपा यादव)

निजी सचिव,

विशेष सचिव,

उच्च शिक्षा विभाग,

उ० प्र० शासन।

Meeting ID: 81370976677

Passcode: 614499

संलग्नक: यथोक्त।

Signed by

Dharm Pal Pandey

Date: 08-11-2024 17:11:34

भवदीय,

(धर्मपाल पाण्डेय)

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ०प्र० शासन।
2. संयुक्त सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ०प्र० शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(धर्मपाल पाण्डेय)
अनुसचिव।

11/08/2024
17:11:34
Dharm Pal Pandey
अनुसचिव

E-3085778/24

No. 35416 /MS/SECY GI/2024

दीप्ति गौड़ मुकर्जी, आईएएस
सचिव
Deepti Gaur Mukerjee, IAS
Secretary



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
New Delhi

संख्या 843 प्रमुख सचिव/व्य.शि.कौ.वि./प्रा.शि./202

पुस्तक पाठ्यक्रम/प्रा.शि./202

D.O.No. PMIS-01/10/2024

30th October, 2024

Dear Shri Singh,

vs (voc Edu)

(स्वीडिज/कृ.पाठ्य) 2024
विशेष सचिव एवं स्टाफ ऑफिसर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

I would like to draw your attention to the Prime Minister's Internship Scheme which was announced in the Budget 2024-25. The scheme aims to provide internship opportunities to one crore youth in the top 500 companies in five years. Through this Scheme, youth will gain exposure for 12 months to real life business environment, across varied professions and employment opportunities.

07/11/24

2. As an initiation of this ambitious Scheme, a pilot project targeted at providing 1.25 lakh internship opportunities for the financial year 2024-25 has been launched on 3rd October, 2024. The feedback received and the evaluation of outcomes during the implementation of the pilot project would be factored in while rolling out the full-fledged PM Internship Scheme. A copy of the guidelines issued on 3rd October, 2024 which were also addressed to you with a request to nominate a nodal officer for scheme implementation, is enclosed for your kind reference. This scheme is envisaged as a central sector scheme and would be in addition to other similar schemes, if any, being implemented in your State.

आलोचनात्मक प्रमुख, व्यावसायिक शिक्षा, और उद्यमशीलता

JS/US

with letter to P.V.C (15)

Youth eligible under the scheme are those who are between 21-24 years of age and are not in full time employment or education. Further, no member of their family should be a government employee or have an income of more than 8 lakh in the financial year 2023-24. Under the scheme, every intern will receive a monthly allowance of Rs. 5000 (out of which Rs. 4500 is to be paid by the Ministry of Corporate Affairs, and Rs. 500 by the company from its CSR funds) as monthly allowance, along with Rs. 6000 as a one-time grant for incidentals, to be paid by the Government. The training cost is to be borne by the Company, from its CSR funds. Further, insurance coverage shall be provided to each individual intern under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, for which premium amount shall be provided by the Central Government.

17.11.2024


4. The pilot project is being implemented through an online portal www.pminternship.mca.gov.in. Companies have offered about 1.27 lakh internship opportunities covering 25 sectors, 36 States/ UTs and 745 districts. The internship opportunities have been offered for youth who have passed High school (about 31,500), Higher Secondary (8,826), ITI certificate holders (about 30,448), Diploma holders (about 21,222) and Graduates (about 35,050). At present the process of registration and applications for internship is going on. Youth are able to explore the opportunities available, and apply for the offers as per their preferences and skills. At the national level, more than 2 lakh internship applications have been received so far. The number of internship opportunities offered by the top companies in your state are about 8506. The details of the opportunities offered in your state are attached.

2000
जी.मि.सी.
8-11-24

5. This scheme is an excellent opportunity for youth living in various districts of your state to gain exposure to business environment of top companies, enhance their technical and behavioural skills thereby improving their employability. I would request you to nominate a nodal Department for this scheme, as the opportunities offered are across all levels of education and requires a coordinated approach at the state level. We would collaborate with the above Department and seek their valuable support in implementing the scheme. We look forward to working with you so that the youth of your State are able to avail the unique opportunity offered by the Prime Minister's Internship Scheme – Pilot Project.

With regards,

Yours Sincerely,


(Deepti Gaur Mukerjee)

Encl: As above.

Shri Manoj Kumar Singh
Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
Lal Bahadur Shastri Bhawan
Lucknow – 226 001

District wise Internship Opportunity offered in UTTAR PRADESH in PM Internship Scheme- Pilot Project		
Sr. No	District/ Qualification	Number of Internship Opportunities
1	Agra	274
	10th	107
	12th	50
	Diploma	10
	Graduation	77
	ITI	30
2	Aligarh	131
	10th	54
	12th	4
	Diploma	17
	Graduation	16
	ITI	40
3	Ambedkar Nagar	137
	10th	11
	Diploma	32
	Graduation	37
	ITI	57
4	Amethi	125
	10th	10
	Diploma	15
	Graduation	9
	ITI	91
5	Amroha	16
	10th	10
	Graduation	2
	ITI	4
6	Auraiya	209
	10th	68
	12th	56
	Diploma	14
	Graduation	49
7	Ayodhya	50
	10th	11
	Diploma	3
	Graduation	15
	ITI	21
8	Azamgarh	25
	10th	16
	Graduation	7
	ITI	2
9	Baghpat	27

	10th	10
	Diploma	2
	Graduation	11
	ITI	4
10	Bahraich	18
	10th	12
	Graduation	4
	ITI	2
11	Ballia	32
	10th	9
	12th	2
	Diploma	6
	Graduation	4
	ITI	11
12	Balrampur	43
	10th	9
	12th	1
	Graduation	5
	ITI	28
13	Banda	45
	10th	12
	Diploma	15
	Graduation	7
	ITI	11
14	Bara Banki	86
	10th	12
	12th	1
	Diploma	15
	Graduation	5
	ITI	53
15	Bareilly	189
	10th	78
	12th	18
	Diploma	13
	Graduation	56
	ITI	24
16	Basti	35
	10th	12
	Graduation	21
	ITI	2
17	Bhadohi	10
	10th	8
	ITI	2
18	Bijnor	55

	10th	20
	12th	1
	Graduation	15
	ITI	19
19	Budaun	24
	10th	14
	Graduation	8
	ITI	2
20	Bulandshahr	53
	10th	15
	12th	3
	Diploma	6
	Graduation	10
	ITI	19
21	Chandauli	14
	10th	9
	12th	2
	Graduation	1
	ITI	2
22	Chitrakoot	14
	10th	11
	Diploma	1
	Graduation	2
23	Deoria	19
	10th	14
	12th	1
	Graduation	2
	ITI	2
24	Etah	33
	10th	18
	Diploma	1
	Graduation	6
	ITI	8
25	Etawah	46
	10th	9
	Diploma	6
	Graduation	4
	ITI	27
26	Farrukhabad	19
	10th	16
	Graduation	1
	ITI	2
27	Fatehpur	39
	10th	11

	Graduation	7
	ITI	13
36	Hardoi	84
	10th	13
	Diploma	8
	Graduation	31
	ITI	32
37	Hathras	62
	10th	26
	Diploma	7
	Graduation	11
	ITI	18
38	Jalaun	25
	10th	10
	Diploma	3
	Graduation	2
	ITI	10
39	Jaunpur	21
	10th	17
	12th	1
	Graduation	1
	ITI	2
40	Jhansi	42
	10th	32
	12th	1
	Diploma	3
	Graduation	2
	ITI	4
41	Kannauj	21
	10th	14
	Graduation	2
	ITI	5
42	Kanpur Dehat	82
	10th	13
	12th	8
	Diploma	26
	Graduation	20
	ITI	15
43	Kanpur Nagar	357
	10th	150
	12th	29
	Diploma	36
	Graduation	103
	ITI	39

44	Kasganj	11
	10th	7
	Graduation	1
	ITI	3
45	Kaushambi	41
	10th	8
	Graduation	28
	ITI	5
46	Kheri	59
	10th	15
	Diploma	2
	Graduation	12
	ITI	30
47	Kushinagar	16
	10th	13
	ITI	3
48	Lalitpur	14
	10th	11
	ITI	3
49	Lucknow	1082
	10th	348
	12th	62
	Diploma	91
	Graduation	497
	ITI	84
50	Mahoba	10
	10th	8
	Graduation	1
	ITI	1
51	Mahrajganj	18
	10th	11
	12th	1
	Graduation	6
52	Mainpuri	36
	10th	14
	Diploma	5
	Graduation	4
	ITI	13
53	Mathura	74
	10th	60
	12th	2
	Graduation	1
	ITI	11
54	Mau	14

	10th	11
	ITI	3
55	Meerut	143
	10th	95
	12th	5
	Diploma	7
	Graduation	20
	ITI	16
56	Mirzapur	15
	10th	13
	ITI	2
57	Moradabad	116
	10th	67
	12th	10
	Diploma	7
	Graduation	12
	ITI	20
58	Muzaffarnagar	91
	10th	26
	Diploma	16
	Graduation	32
	ITI	17
59	Pilibhit	32
	10th	30
	ITI	2
60	Pratapgarh	37
	10th	11
	Graduation	14
	ITI	12
61	Prayagraj	223
	10th	76
	12th	12
	Diploma	40
	Graduation	29
	ITI	66
62	Rae Bareli	157
	10th	14
	Diploma	39
	Graduation	33
	ITI	71
63	Rampur	30
	10th	9
	Diploma	3
	Graduation	1

	ITI	17
64	Saharanpur	50
	10th	15
	Diploma	2
	Graduation	10
	ITI	23
65	Sambhal	23
	10th	9
	12th	2
	Diploma	2
	Graduation	2
	ITI	8
66	Sant Kabir Nagar	8
	10th	8
67	Shahjahanpur	43
	10th	15
	12th	12
	Diploma	3
	Graduation	5
	ITI	8
68	Shamli	16
	10th	9
	Diploma	1
	Graduation	2
	ITI	4
69	Shrawasti	8
	10th	8
70	Siddharthnagar	9
	10th	9
71	Sitapur	62
	10th	16
	12th	1
	Diploma	5
	Graduation	12
	ITI	28
72	Sonbhadra	645
	10th	21
	12th	15
	Diploma	139
	Graduation	16
	ITI	454
73	Sultanpur	19
	10th	11
	12th	4

	Graduation	1
	ITI	3
74	Unnao	19
	10th	10
	Graduation	5
	ITI	4
75	Varanasi	265
	10th	126
	12th	41
	Diploma	4
	Graduation	82
	ITI	12
	Total Internship opportunity in the State	8506

F. NO- CSR/ 13/35/2024
Government of India
Ministry of Corporate Affairs
(PMIS Cell)

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhawan,
Dr. Rajendra Prasad Road,
New Delhi-110 001

Dated: 03.10.2024

Office Memorandum

Subject: Guidelines for "Prime Minister's Internship Scheme - Pilot Project (Financial Year 2024-25)"

The Prime Minister's Internship Scheme in Top Companies has been announced in the Budget 2024-25 (Scheme). It aims to provide internship opportunities to one crore youth in top 500 companies in five years. Through this Scheme, youth will gain exposure for 12 months to real-life business environment, across varied professions and employment opportunities.

2. As an initiation of this ambitious Scheme which involves multiple stakeholders and innovative concepts of skilling, a Pilot Project of the Scheme targeted at providing 1.25 lakh internship opportunities is being launched for the Financial Year (FY) 2024-25. The top companies for this Pilot Project have been identified on the basis of the average of CSR expenditure of the last three years. Participation of the companies in this Scheme is voluntary. A list of these companies would be uploaded on the PM Internship Scheme Portal.

3. Internship, for the purpose of this Scheme is envisaged as an arrangement between the intern and the company in which the company provides an opportunity to the intern to get training, gain experience and skills within the real-life environment of the business or organization that helps in bridging the gap between academic learning and industry requirements, in turn, assisting enhancement of her/his employability.

4. **Scope:** The Scheme is separate from all the existing schemes related to skill development, apprenticeships, internship and student training programmes, etc. being implemented across all the States & UTs of India, and will run independently of all such Central/State schemes.

5. **Salient Features of the Pilot Project**

5.1 **Internship Duration:** Duration of the Internship shall be 12 months. At least half of the internship period must be spent in the actual working experience/ job environment, and not in the classroom.

5.2 Eligibility criteria for candidates

5.2.1 Age: Youth aged between 21 and 24 (as on the last date for submission of application), belonging to Indian nationality, who are not employed full-time and not engaged in full-time education. Candidates enrolled in online/ distance learning programmes are eligible to apply.

5.2.2 Educational Qualifications: Candidates who have passed High School, Higher Secondary School, possess a certificate from an ITI, hold a diploma from a Polytechnic Institute, or are graduates with degrees such as BA, B.Sc, B.Com, BCA, BBA, B.Pharma, etc. are eligible.

5.2.3 Ineligibility criteria: The following persons are ineligible to participate:

- (i) Graduates from IITs, IIMs, National Law Universities, IISER, NIDs, and IIITs.
- (ii) Those having qualifications such as CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA, any master's or higher degree.
- (iii) Those undergoing any skill, apprenticeship, internship or student training programme under Central Government or State Government schemes.
- (iv) Those who have completed apprenticeship, training under National Apprenticeship Training Scheme (NATS) or National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) at any point.
- (v) If the income of any of the family members of the candidate exceeds Rs 8 lakh for FY 2023-24.
- (vi) If any member of the family is a permanent/regular government employee.

Note: For the purposes of the Pilot Project:

- (i) "Family" means self, parents and spouse.
- (ii) "Government" means Central and State Governments, UT administration, Central and State PSUs, statutory organizations, local bodies etc.
- (iii) "Employee" means regular/ permanent employees but does not include contractual employees.

5.3 Criteria for the companies (Partner Companies) to participate

5.3.1 The top 500 companies have been identified by the Ministry on the basis of their average CSR expenditure of the last three years. Apart from these, any other company/ bank/ financial institution desirous of participating in the Scheme, may do so with the approval of the Ministry of Corporate Affairs (MCA), which would take a view keeping in view under represented sectors and areas in the above mentioned 500 companies.

5.3.2 In case the Partner Company cannot directly provide such internship opportunities in its own company, it may tie-up with:

- Companies in its forward and backward supply chain (e.g. suppliers/ customers/ vendors), or;

- Other Companies/Institutions in its Group; or otherwise.

5.4 Support and Benefits: This is a Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme. Details of the support, financial benefits and funding pattern under the Scheme are given below:

5.4.1 Monthly assistance to the interns: Monthly assistance of Rs. 5,000 will be paid to the interns for the entire duration of 12 months of the internship. Out of this, every month the company, based on the attendance and related company policies regarding good conduct, etc. will release Rs.500/- to each intern from the Company's CSR funds. Once the Company makes the payment, the Government will pay Rs.4,500 to the candidate through Direct Benefit Transfer to the intern's Aadhaar seeded bank account. In case, any Company wishes to provide monthly assistance over and above Rs.500, it may do so from its own funds.

5.4.2 Grant for incidentals: A one-time grant for incidentals of ₹6,000 will be disbursed to each intern by the government through Direct Benefit Transfer, upon the intern's joining at the internship location.

5.4.3 Training cost: Expenditures associated with the training of interns under the Scheme, would be borne by the company from its CSR funds, as per the extant rules.

5.4.4 Administrative cost: As covered under Companies (CSR Policy) Rules, 2014, up to 5% of the CSR expenditure incurred under this Scheme may be booked as administrative costs by the company.

5.4.5 Insurance coverage: Insurance coverage shall be provided to each individual intern under insurance schemes of the Government of India, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, for which premium amount shall be provided by Government. In addition, the company may also provide additional accidental insurance coverage to the interns.

5.5 Implementation Mechanism

5.5.1 The Scheme will be implemented through an online portal (www.pminternship.mca.gov.in) developed by the Ministry of Corporate Affairs. The Portal will serve as a centralized platform for end-to-end Scheme implementation and internship lifecycle management.

5.5.2 Process for posting internship opportunities: A dedicated dashboard will be provided to each Partner Company on the Portal, for posting Internship opportunities. The Internship opportunities would contain details of the internships being offered, such as location of the internship, nature of the internship, minimum educational qualification required, any facilities provided by the company, etc.

5.5.3 Registration/Application Process for the candidates: Eligible candidates would have to register themselves on the Portal. Based on the information provided by the candidates, a resume will be generated by the Portal. A browsing facility will be made available to candidates

for preferred sectors, functional roles, locations, and other criteria. Candidates may then apply for up to five (5) internship opportunities based on their preferences, including location (state, district), sector, functional role, and qualifications.

5.5.4 Shortlisting and Selection: A pool of candidates would be shortlisted for each internship opportunity through the Portal. The shortlisting process will be based on the candidates' preferences and the requirements posted by the companies. In the shortlisting process, criteria that prioritize lower employability and ensure broader representation across the applicant base will be considered. The shortlisting criteria is aimed at promoting diversity and social inclusivity in the internship program. To ensure the above, the Portal will use tools to give representation to all such segments of the population, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes as well as Persons with Disabilities. Depending on the number of offers for each internship, approximately twice /thrice as many names, along with the Resume of the candidates, will be sent to the company for selection. Companies would be able to select candidates and make internship offers based on their respective selection criteria and processes. Once an offer is sent by the company to the candidate, the candidate will be able to convey acceptance through the Portal. A Detailed Implementation Mechanism for the Pilot Project is given in Annexure-I. This mechanism would be as prescribed by this Ministry.

5.5.5 It is clarified that an offer of internship would not give rise to any contractual or legal relationship of employer-employee between the Ministry, or the concerned company, and the selected intern. It is further clarified that such an offer of internship can neither be construed to be in the nature of an offer or promise of future employment by the concerned company or Ministry, during or after the period of internship.

5.5.6 Operational Guidelines: Detailed operational guidelines for the companies and the youth to participate in the Pilot Project through the Portal, will be provided on the Portal.

5.6 Recognition of Best Practices: The Ministry will establish a transparent process to recognize and award interns, companies based on their exceptional performance, innovation, and other criteria.

5.7 Grievance Redressal Mechanism: A grievance redressal mechanism to address the concerns and issues faced by stakeholders will be established to ensure timely resolution and enhance overall satisfaction of the users. The key features of the grievance redressal system are listed below:

- i) **Internship Portal:** All stakeholders including interns, companies, etc. will be able to submit their queries or grievances via the query redressal tools including chatbots linked to the Portal. These tools are envisaged to facilitate easy registration of the queries, real time tracking, and updates on the resolution status.
- ii) **Dedicated call Centre:** A multilingual call center will be established to address grievances/ queries received through the helpline.

6. Administrative and Monitoring framework

6.1 There shall be a Monitoring and Steering Committee (MSC) to oversee design, implementation, operations, and other aspects of the Scheme. The MSC will comprise of officers from MCA, other Ministries/ Departments and representatives from the industry. The MSC will be empowered to make recommendations including but not limited to any modifications in the guidelines, eligibility, selection criteria, communication and outreach strategy, monitoring, evaluation, etc of the Pilot Project. The Ministry may also constitute any other committee(s) for effective Scheme implementation, review, and coordination.


6.2 A concurrent monitoring, evaluation and learning (MEL) framework shall be developed so that timely corrective actions may be taken. A dashboard indicating key performance indicators (KPIs); periodic data reports and performance scorecards shall be used to regularly monitor and evaluate the end-to-end implementation across all fronts. Independent evaluation as well as periodic assessment/ evaluation studies will be undertaken.

7. **Communication, Awareness and Capacity Building:** Communication, advocacy, and capacity-building initiatives will be undertaken to effectively promote the Scheme to raise awareness and highlight its benefits. FAQs, user manuals, instructional videos, and informational materials will be provided on the Portal to facilitate participation of candidates and industry.

8. **Coordination with the State Governments:** Coordination with the State Governments/ PRIs/ ULBs would be done as per requirements.

9. **Learnings from the Pilot Project:** Keeping in mind the volume and complex nature of the Scheme, Pilot Project is a pivotal phase that allows for testing concepts, strategies and systems before a full-scale implementation. Based on the feedback received and evaluation of outcomes during the implementation of the Pilot Project, lessons drawn shall be collated by the Ministry. The same will be factored in while rolling out the first phase of the PM Internship Scheme, as announced in the Budget 2024-25.

10. This issues with the approval of Hon'ble Minister of Corporate Affairs.


(Anuradha Thakur)
Additional Secretary

To,

1. Director General of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs
2. All Regional Directors and
3. All Registrar of Companies.

Copy to:

1. Finance Secretary and Secretary, Department of Public Enterprises
 2. Secretary, Coordination, Cabinet Secretariat
 3. Secretary, Department of Economic Affairs
 4. Secretary, Department of Expenditure
 5. Secretary, Department of Financial Services
 6. Secretary, Ministry of Labour & Employment
 7. Secretary, Department of Higher Education
 8. Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
 9. Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports
 10. Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology
 11. All the Chief Secretaries of the State Governments/ UTs with the request to nominate a nodal officer for the Scheme.
 12. Shri Saurabh Shukla, Director, Prime Minister Office
 13. PS to Hon'ble Minister of Corporate Affairs
 14. PS to Hon'ble Minister of State of Corporate Affairs
 15. PPS to Cabinet Secretary
 16. Chief Controller of Accounts, M/o Corporate Affairs
 17. Guard File
-

Annexure-I

Implementation Mechanism

Ministry of Corporate Affairs shall develop the Portal available at www.pminternship.mca.gov.in. The Portal will serve as a centralized platform for end-to-end Scheme implementation and internship lifecycle management.

2. A broad overview of the Portal and other implementation processes is given below:

2.1 List of Partner Companies: The list of Partner Companies shall be displayed on the Portal.

2.2 Internship opportunities: Internship opportunities may be posted by the Partner Companies on the Portal. The Internship opportunities would contain details of the internships being offered, such as location of the internship, roles/ functions of the internship, minimum educational qualification required, other special requirement, any facilities provided by the company etc.

2.3 Candidate Registration and Profile Creation: Candidates must first be registered on the Portal through Aadhaar authentication or eKYC. Information such as name, address, educational qualifications, certifications (if any), and other relevant details to be provided by the candidates as specified on the Portal. Proof of educational qualifications and certifications would have to be uploaded by the candidates. Additionally, candidates must submit a self-declaration on the Portal, affirming that all eligibility requirements specified in these guidelines are met and that none of the ineligibility criteria apply. Based on the submitted details, a Resume will be generated by the Portal for the candidate.

2.4 Candidate Application: After the Aadhaar authentication by the candidates, a browsing facility will be made available to candidates for browsing through internship opportunities, based on their preferred sectors, functional roles, locations, and other criteria. Candidates may then apply for up to five (5) internship opportunities based on their preferences, including location (state, district), sector, functional role, and qualifications.

2.5 Shortlisting of Candidates: A pool of candidates would be shortlisted for each internship opportunity by the Portal. Depending on the number of offers for each internship, approximately twice/thrice as many applications would be shortlisted to be sent to the company. In the shortlisting process, criteria that prioritize lower employability and ensure broader representation across the applicant base will be considered. The shortlisting criteria is aimed at promoting diversity and social inclusivity in the internship program. To ensure the above, the Portal will use tools to give representation to all such segments of the population, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes as well as Persons with Disabilities

2.6 This pool of shortlisted candidates would then be forwarded to each company for selection.

2.7 Selection of Candidates: From the shortlisted group, companies would be able to choose candidates based on their respective selection criteria and processes. Internship offers to the candidates to be sent by the Company through the Portal. Once an offer is sent by the company to the candidate, the candidate would be able to convey acceptance through the Portal. A candidate may receive up to two (2) internship offers in one cycle. A model format of the Offer Letter will be available on the Portal for the companies to use.

2.8 Internship Document Generation: Upon a candidate's acceptance of the offer, the Portal would automatically generate an Internship Document that clearly outlines the details of the internship, including the roles and responsibilities of both the intern and the company. A model format of the Internship Document will be available on the Portal.

2.9 Internship Joining: Once the candidate joins the internship, the company would confirm this on the Portal. This confirmation will initiate the release of ₹6,000 as a grant for incidentals, which will be disbursed to the candidate by the government through Direct Benefit Transfer.

2.10 Internship: Each month, the company will pay ₹500 and report this payment on the Portal. Following this confirmation, ₹4,500 will be released by the government, which would be disbursed to the candidate through Direct Benefit Transfer (DBT).

2.11 Completion & Certification: Upon successfully completing the internship, a Certificate of Completion would be issued by the Partner Company to the candidate. A model format of the Certificate will be available on the Portal. The Certificate shall be issued only by the participating Partner Companies.

3. Guidelines for the Companies

3.1 The company is expected to provide the person an actual working experience on a skill in which the company is directly involved. It shall be strictly ensured that at least half of the internship period would be in the actual work/ real-life business environment, not in classroom.

3.2 In case the company cannot directly provide internship opportunities, it may tie-up with:

- Companies in its forward and backward supply chain (e.g. suppliers/ customers/ vendors) or
- Other companies/institutions in its group; or otherwise.

3.3 Companies are advised not to prescribe qualification higher than necessary for the internship.

3.4 Companies must not offer internships for unskilled roles such as cleaning, delivery, porter, security guard, office boy etc.

3.5 Companies are advised to ensure that the internship offered under PM Internship Scheme is separate from other skill / apprenticeship/ internship/ student training programme offered by them under any other Central Government or State Government scheme.

3.6 Supervisors or mentors must be assigned by the companies to each intern upon joining. Additionally, companies are encouraged to provide or enhance the soft and employability skills of each intern.

3.7 The participating Partner Companies are expected to steer the internship management programme and the different internship opportunities offered across their company and others in their forward and backwards supply chain (e.g. suppliers/ customers/ vendors) or other companies/ institutions in its group.

3.8 Companies shall follow their own mechanism for assessing the candidates on a periodic basis. Quarterly Assessment Report of the candidates would have to be uploaded by the company on the Portal.

3.9 In case an intern **withdraws or drops out** of the internship before completion, the company must communicate this information to the government via the Portal by marking the intern as a 'Dropout'. This will ensure that no further payments are disbursed to the candidate, by the government. The company's standard policies regarding attendance, code of conduct, and dropout shall be applied. **Generally, an intern will be considered a dropout if they stop attending to their internship requirements suddenly and without notice to their Mentor/ supervisor and fail to respond and/or rejoin despite two attempts at communication over a reasonable period by the mentor or supervisor, or if they express an unwillingness to continue.** Such candidates will not be permitted to rejoin, and no Internship Certificate will be issued to them. Furthermore, they will be disqualified from applying for any internship for one year under this Scheme.

3.10 It is clarified that an offer of internship would not give rise to any contractual or legal relationship of employer-employee between the Ministry, or the concerned company, and the selected intern. It is further clarified that such an offer of internship can neither be construed to be in the nature of an offer or promise of future employment by the concerned company or Ministry, during or after the period of internship.

4. Guidelines for the Candidates

4.1 The rules and regulations of the establishment, including those related to timings, holidays, leaves, conduct, and discipline, shall be adhered to by the intern.

4.2 In case of a medical emergency, the demise of a family member, or such extenuating and emergency circumstances, a sabbatical of up to two months may be granted to the intern, in accordance with company policies and/or any directives issued by the Ministry from time to time. No financial assistance shall be provided during the sabbatical period; however, the intern shall be permitted to rejoin and complete the remaining duration of the overall 12-month

internship period. If the sabbatical period exceeds two months, the candidate will be required to discontinue and may reapply in the next internship offer cycle.

5. Recognition of performance: Interns will undergo continuous evaluation of their performance and conduct by the companies in accordance with the companies' policies. To build confidence and create aspirational value for the Scheme, companies are encouraged to recognize the outstanding interns, and this recognition may be displayed on the companies' websites and on this Portal.

वी०सी० दिनांक 11.11.2024 अपराह्न 03.30 बजे

प्रेषक,

धर्मपाल पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1 - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/शिक्षा विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग/ समाज कल्याण विभाग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3 - क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय (RDSDE), कानपुर नगर।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ दिनांक: 11 नवम्बर, 2024

विषय: भारत सरकार की "प्रधानमंत्री इन्टरनशिप योजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु आयोजित वीडियो कन्फ्रेंसिंग बैठक के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग के पत्र संख्या- आई/790997/2024-89-1099/465/2024 दिनांक 08.11.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि "प्रधानमंत्री इन्टरनशिप योजना" के सफल क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2024 को अपराह्न 03.30 बजे वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आहूत की गयी है।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार आहूत वी०सी० में शासन स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर/संबंधित विश्वविद्यालय के भिन्न अधिकारियों को सुसंगत

सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। बैठक हेतु लिंक एवं पासवर्ड निम्नवत् है:-

Join Zoom Meeting
[https://us06web.zoom.us/j/83321466324?](https://us06web.zoom.us/j/83321466324?pwd=HqdeVFVAbGG5VQNB9JAY9OIZkhWqL1.1)
pwd=HqdeVFVAbGG5VQNB9JAY9OIZkhWqL1.1

Meeting ID: 833 2146 6324
Passcode: 491872

Signed by
Dharm Pal Pandey
Date: 11-11-2024 12:59:01

भवदीय,
(धर्मपाल पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव / विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ०प्र० शासन।
2. संयुक्त सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ०प्र० शासन ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(धर्मपाल पाण्डेय)
अनु सचिव।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उम्मीदवारों के लिए:

सामान्य जानकारी:

1. प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना (पीएमआईएस) क्या है?

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटरशिप के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक जीवन के व्यावसायिक वातावरण से परिचित कराता है, जिससे उन्हें मूल्यवान कौशल और कार्य अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में युवाओं को एक करोड़ इंटरशिप प्रदान करना है।

2. इंटरशिप क्या है? मुझे इंटरशिप क्यों करनी चाहिए?

इंटरशिप इंटरन और कंपनी के बीच एक व्यवस्था है जिसमें कंपनी इंटरन को व्यवसाय या संगठन के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है, और बदले में उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है।

3. प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के माध्यम से मुझे किस प्रकार की इंटरशिप मिलेगी?

योग्य उम्मीदवारों को आईटी और सॉफ्टवेयर विकास, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, तेल, गैस और ऊर्जा, धातु और खनन, एफएमसीजी (फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स), दूरसंचार, बुनियादी ढांचा और निर्माण, खुदरा और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, सीमेंट और निर्माण सामग्री, ऑटोमोटिव, फार्मास्युटिकल, विमानन और रक्षा, विनिर्माण और औद्योगिक, रसायन, मीडिया, मनोरंजन और शिक्षा, कृषि और संबद्ध, परामर्श सेवाएं, कपड़ा विनिर्माण, रत्न और आभूषण, यात्रा और आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमिकाओं में इंटरशिप मिलेगी। *विभिन्न क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने वाली कंपनियों को देखने के लिए यहां क्लिक करें।*

4. मुझे किस तरह की कंपनियों में इंटरशिप करने का मौका मिलेगा?

चयनित उम्मीदवारों को भारत भर की शीर्ष 500 कंपनियों के साथ इंटरशिप करने का अवसर मिलेगा। इन उद्योग-अग्रणी कंपनियों के साथ इंटरशिप करने से आपको बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने, नए कौशल हासिल करने और महत्वपूर्ण पेशेवर नेटवर्क बनाने का

मौका मिलेगा। कंपनी अपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड सप्लाई चेन और अपने समूह की अन्य कंपनियों में या अन्यथा इंटरशिप भी प्रदान कर सकती है।

5. इंटरशिप की अवधि क्या है?

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत इंटरशिप एक वर्ष (12 महीने) की अवधि के लिए होगी।

6. क्या मैं अपनी इंटरशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा?

इंटरशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा (6 महीने) वास्तविक कार्य अनुभव/नौकरी के माहौल में बिताया जाना चाहिए, न कि कक्षा में। जबकि इंटरशिप के एक निश्चित हिस्से में प्रासंगिक प्रशिक्षण शामिल होगा, आपकी इंटरशिप की एक महत्वपूर्ण अवधि (कम से कम 6 महीने) पेशेवर सेटअप में वास्तविक दुनिया के अनुभव पर केंद्रित होगी।

7. क्या मुझे इंटरशिप के बाद नौकरी मिलेगी?

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना भारत में शीर्ष कंपनियों के साथ काम करके अपने कौशल को सीखने और बढ़ाने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। हालाँकि यह योजना पूरी होने पर नौकरी की गारंटी नहीं देती है, लेकिन इंटरशिप के दौरान आपके द्वारा विकसित ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और पेशेवर नेटवर्क आपके करियर की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देंगे।

पात्रता मापदंड:

8. क्या मैं प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

- आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आपकी आयु 21-24 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक)।
- आपको पूर्णकालिक रूप से नौकरी में नहीं होना चाहिए या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए (ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार पात्र हैं)।
- आपने अपना माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) या इसके समकक्ष, उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (एचएससी) या इसके समकक्ष पूरा किया होगा, या आपके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से प्रमाणपत्र, पॉलिटेक्निक

संस्थान से डिप्लोमा, या बीए, बीएससी , बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा आदि जैसे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

[अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।](#)

9. क्या अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

10. यदि मैं ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित हूं तो क्या मैं इंटरनशिप अवसर के लिए आवेदन कर सकता हूं?

हां, ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार शिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

11. क्या विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है?

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना में औपचारिक आरक्षण प्रावधान नहीं है, लेकिन पोर्टल को विविधता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एल्गोरिदम एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों सहित आबादी के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया विविधता और समावेश पर जोर देती है, जिससे कंपनियों को अपने स्वयं के मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने की अनुमति मिलती है, जबकि पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि इंटरनशिप के लिए विविध पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों पर विचार किया जाए। यह दृष्टिकोण कार्यक्रम में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में मदद करता है।

अयोग्यता मानदंड:

12. प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

आप प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं यदि:

- आपकी आयु 21 वर्ष से कम या 24 वर्ष से अधिक होनी चाहिए (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार)।
- आप वर्तमान में पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में लगे हुए हैं।
- आपने आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आईआईएसईआर, एनआईडी या आईआईआईटी जैसे विशिष्ट संस्थानों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।

- आपके पास उन्नत योग्यताएं जैसे सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, पीएचडी, या कोई मास्टर डिग्री या उच्च योग्यता (यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त) हो।
- आप किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत कोई कौशल, प्रशिक्षता, इंटरशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं।
- आपने पहले ही राष्ट्रीय प्रशिक्षता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) या राष्ट्रीय प्रशिक्षता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत प्रशिक्षता पूरी कर ली है।
- आपके परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹8 लाख से अधिक है।
- आपके परिवार का कोई भी सदस्य (स्वयं, माता-पिता या पति/पत्नी) स्थायी/नियमित सरकारी कर्मचारी है (अनुबंधित कर्मचारियों को छोड़कर)। "सरकार" में केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), वैधानिक संगठन और स्थानीय निकाय शामिल हैं।

[अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।](#)

13. यदि मैं ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित हूं तो क्या मैं इंटरशिप अवसर के लिए आवेदन कर सकता हूं?

हां, ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार शिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

14. क्या मास्टर डिग्री होने से मुझे प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी?

मास्टर डिग्री या सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पीएम इंटरशिप योजना के तहत इंटरशिप के अवसर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

वित्तीय सहायता:

15. क्या मुझे इंटरशिप करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी?

इंटरशिप में शामिल होने के बाद, प्रत्येक इंटरन को 12 महीने की इंटरशिप की पूरी अवधि के लिए ₹5,000 की मासिक सहायता मिलेगी। इस राशि में से:

- साझेदार कंपनियां इंटरन की उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर हर महीने 500 रुपये जारी करेंगी।

- एक बार कंपनी द्वारा भुगतान कर दिए जाने के बाद, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रशिक्षु के आधार से जुड़े बैंक खाते में 4,500 रुपये का भुगतान करेगी।
- इंटरशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटरन को भारत सरकार द्वारा **₹6,000 का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा**। इंटरशिप में शामिल होने के बाद यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- भारत सरकार की बीमा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत इंटरन को बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी इंटरन को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है।

16. क्या मुझे इंटरशिप की अवधि के दौरान यात्रा भत्ता या अन्य सहायता मिलेगी?

- भागीदार कंपनियाँ अपने विवेक के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता या कोई अन्य सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकती हैं। आपके द्वारा चुनी गई इंटरशिप में कोई अन्य लाभ जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी।
- इंटरशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटरन को भारत सरकार द्वारा ₹6,000 का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान आपकी इंटरशिप यात्रा की शुरुआत में आपकी सहायता करने के लिए है।
- अपनी इंटरशिप के दौरान आपको ₹5,000 की मासिक सहायता मिलेगी।

17. क्या इंटरशिप के बाद भी बीमा कवर जारी रहेगा?

नहीं, आपकी इंटरशिप पूरी होने पर बीमा का लाभ समाप्त हो जाएगा।

18. क्या मुझे अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी?

अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

19. क्या मुझे अपनी इंटरशिप के लिए कपड़े खरीदने के लिए कोई वित्तीय सहायता मिलेगी?

कपड़ों की खरीद के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। हालाँकि, आपके इंटरशिप में शामिल होने के बाद, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में ₹6000 का एकमुश्त अनुदान हस्तांतरित किया जाएगा।

20. आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है?

विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग आवश्यक है। *आधार सीडिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ क्लिक करें*

आवेदन प्रक्रिया:

21. इंटर्न का चयन कैसे किया जाएगा?

इंटरन का चयन एक उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष, सामाजिक रूप से समावेशी और तकनीक-संचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार पीएम इंटरनशिप पोर्टल (<https://pminternship.mca.gov.in/>) पर पंजीकरण करेंगे, अपना प्रोफाइल पूरा करेंगे, अपना सीवी तैयार करेंगे और उपलब्ध अवसरों की सूची में से अपनी प्राथमिकताएँ प्रस्तुत करेंगे।

- शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं और कंपनियों द्वारा पोस्ट की गई आवश्यकताओं पर आधारित होगी। शॉर्टलिस्टिंग मानदंड का उद्देश्य इंटरनशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। पोर्टल एससी, एसटी, ओबीसी के साथ-साथ दिव्यांगों सहित आबादी के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपकरणों का उपयोग करता है।
- प्रत्येक इंटरनशिप के लिए प्रस्तावों की संख्या के आधार पर, लगभग दोगुने/तीनगुने नाम, उम्मीदवारों के बायोडाटा के साथ, चयन के लिए कंपनी को भेजे जाएंगे।
- इसके बाद वे उम्मीदवारों का चयन करेंगे और उनके संबंधित चयन मानदंडों के आधार पर इंटरनशिप की पेशकश करेंगे।

22. पीएम इंटरनशिप योजना पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

पात्र अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए:

- आधार कार्ड
- शैक्षिक प्रमाण पत्र (पूर्णता / अंतिम परीक्षा / मूल्यांकन प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा)
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो (वैकल्पिक)

अन्य बातों के लिए स्व-घोषणा ही पर्याप्त होगी। किसी दस्तावेज़ के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

23. मैं कितने इंटरनशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

अभ्यर्थी अधिकतम 5 इंटरशिप विकल्पों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका चयन उनके पसंदीदा स्थान, क्षेत्र, भूमिका और योग्यता के आधार पर किया जा सकता है।

24. क्या मैं पोर्टल पर अपनी पांच इंटरशिप प्राथमिकताओं को बदल सकता हूँ?

हां, आप आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पोर्टल पर अपनी पांच प्राथमिकताओं को जितनी बार चाहें बदल सकते हैं। हालाँकि, एक बार अपनी प्राथमिकताएँ सबमिट करने के बाद, आप उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते।

25. यदि मुझे मेरे पांच पसंदीदा अवसरों में से किसी के लिए भी नहीं चुना गया तो क्या होगा?

यदि कोई अभ्यर्थी पांच में से किसी भी अवसर के लिए चयनित नहीं होता है तो वह प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के आगामी चक्रों के लिए पुनः आवेदन कर सकता है।

26. मुझे अधिकतम कितने इंटरशिप ऑफर मिल सकते हैं?

एक उम्मीदवार को अधिकतम दो इंटरशिप ऑफर मिल सकते हैं। एक बार ऑफर मिलने के बाद, उम्मीदवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑफर को स्वीकार/अस्वीकार करना होगा।

27. यदि मैं उस इंटरशिप को स्वीकार नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे चुना गया है तो क्या होगा?

अभ्यर्थी इंटरशिप के अपने प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं। हालांकि, यदि कोई अभ्यर्थी इंटरशिप को अस्वीकार करता है, तो वह प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के भविष्य के चक्रों में ही पुनः आवेदन कर सकेगा।

28. यदि मैं इंटरशिप ऑफर स्वीकार कर लूं तो मुझे अंतिम ऑफर लेटर कैसे मिलेगा?

आपका अंतिम ऑफर लेटर प्रधानमंत्री इंटरशिप पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और साथ ही आपके पंजीकृत ईमेल पते पर अनुलग्नक के रूप में भेजा जाएगा।

अन्य सहायता:

29. क्या इंटरशिप पूरी करने के बाद रोजगार की कोई गारंटी है?

नहीं, प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना इंटरशिप पूरी करने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं देती है। हालाँकि, कंपनियाँ उन इंटरन को रोजगार देने का विकल्प चुन सकती हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान असाधारण प्रदर्शन करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंटरशिप की पेशकश मंत्रालय, कंपनी और इंटरन के बीच कोई संविदात्मक या कानूनी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं बनाती है। इसके अतिरिक्त, इंटरशिप को कंपनी या मंत्रालय द्वारा भविष्य में रोजगार के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

30. क्या मैं इंटरशिप को 12 महीने से आगे बढ़ा सकता हूँ?

नहीं, इंटरशिप की अवधि 12 महीने निर्धारित है। प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

31. क्या मैं अपनी इंटरशिप के दौरान छुट्टियां ले सकता हूँ?

हां, आप साझेदार कंपनी की नीतियों के अनुसार छुट्टियां ले सकते हैं।

32. क्या मुझे छुट्टियाँ मिलेंगी?

हां, चयनित अभ्यर्थी अपनी कंपनी की अवकाश सूची के अनुसार छुट्टियों के लिए पात्र होंगे।

33. चिकित्सा या किसी अन्य आपातस्थिति में मैं क्या करूँ?

ऐसे मामलों में, साझेदार कंपनी की नीतियों के अधीन, प्रशिक्षुओं को दो महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है।

34. क्या मैं अवकाश के बाद पुनः इंटरशिप में शामिल हो सकता हूँ?

हां, यदि अवकाश दो महीने से अधिक न हो तो प्रशिक्षु पुनः शामिल होकर 12 महीने की इंटरशिप अवधि पूरी कर सकते हैं।

35. यदि अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो तो क्या होगा?

यदि अवकाश दो महीने से अधिक है, तो प्रशिक्षु को इंटरशिप बंद करनी होगी। इसके बाद अभ्यर्थी अगले इंटरशिप ऑफर चक्र में फिर से आवेदन कर सकता है।

36. यदि मैं दो महीने से कम का अवकाश लेता हूँ, तो क्या मुझे फिर भी इंटरशिप प्रमाणपत्र मिलेगा?

हां, यदि अवकाश दो महीने से कम है, तो भी अभ्यर्थी को कंपनी की संतुष्टि के अनुसार इंटरशिप पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

37. क्या मैं चिकित्सा संबंधी आपातस्थिति या पारिवारिक समस्याओं के अलावा अन्य कारणों से अवकाश का अनुरोध कर सकता हूँ?

पारिवारिक आपातस्थिति जैसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या ऐसी ही अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में अवकाश दिया जा सकता है। इंटरन को अपनी विशिष्ट स्थिति पर चर्चा करने के लिए अपने पर्यवेक्षक या सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। ब्रेक देने या न देने का अंतिम निर्णय कंपनी पर निर्भर करेगा।

38. यदि मुझे इंटरशिप पूरी होने से पहले ही छोड़नी पड़े तो क्या होगा?

यदि कोई इंटरन इंटरशिप पूरी होने से पहले ही छोड़ देता है, तो उसे अपने पर्यवेक्षक और कार्यक्रम समन्वयक को सूचित करना होगा।

39. यदि मैं इंटरशिप पूरी होने से पहले ही छोड़ दूँ (ड्रॉप आउट हो जाऊँ) तो क्या मुझे इंटरशिप प्रमाणपत्र मिलेगा?

नहीं, इंटरशिप बीच में छोड़ने वाले प्रशिक्षुओं को इंटरशिप समाप्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।

40. क्या मैं अपनी वर्तमान इंटरशिप छोड़ने के बाद पुनः अन्य इंटरशिप के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

यदि आप अपनी वर्तमान इंटरशिप पूरी होने से पहले छोड़ देते हैं, तो आपको अपनी ज्वाइनिंग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पीएम इंटरशिप योजना के तहत किसी अन्य इंटरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

41. क्या मैं एक वर्ष की अवधि के बाद इंटरशिप के लिए पुनः आवेदन कर सकता हूँ?

हां, इंटरशिप छोड़ चुके प्रशिक्षु एक वर्ष के बाद प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत इंटरशिप के लिए पुनः आवेदन करने के पात्र हैं।

42. क्या इंटरशिप शुरू होने से पहले कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा?

नहीं। प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत प्रत्येक इंटरशिप के हिस्से के रूप में प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

43. क्या इंटरशिप के दौरान कोई प्रदर्शन मूल्यांकन होता है?

हां, इंटरन का मूल्यांकन समय-समय पर उनके प्रदर्शन, उपस्थिति और कंपनी की नीतियों के पालन के आधार पर किया जाएगा। इंटरन को पेशेवर रूप से बेहतर बनाने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए फीडबैक प्रदान किया जाएगा। ये मूल्यांकन भागीदार कंपनियों द्वारा किए जाएंगे।

44. एक प्रशिक्षु के रूप में मैं किस तरह की परियोजनाओं पर काम करूंगा?

इंटरन कंपनी की जरूरतों और इंटरन के कौशल के आधार पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर काम करेंगे।

45. इंटरशिप के दौरान मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए?

कंपनी के आधार पर ड्रेस कोड की आवश्यकताएं अलग-अलग हो सकती हैं। आम तौर पर, इंटरन से पेशेवर तरीके से कपड़े पहनने और कंपनी की ड्रेस कोड नीतियों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

46. क्या इंटरशिप पूरी करने के बाद मुझे प्रमाण पत्र मिलेगा?

हां, सफलतापूर्वक इंटरशिप पूरी करने वाले इंटरन को साझेदार कंपनियों से पीएम इंटरशिप योजना के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।

47. मंत्रालय प्रशिक्षुओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर कैसे मान्यता देगा?

मंत्रालय प्रशिक्षुओं को उनके असाधारण प्रदर्शन, नवाचार और अन्य मानदंडों के आधार पर मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करेगा।

48. मेरी शिकायत या प्रश्नों का समाधान कैसे होगा?

इंटरन अपनी शिकायतें या प्रश्न इंटरनेशिप पोर्टल पर चैटबॉट सहित शिकायत निवारण उपकरणों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर उपलब्ध होगा। यह प्रणाली प्रश्नों के आसान पंजीकरण, वास्तविक समय ट्रेकिंग और समाधान की स्थिति पर अपडेट की सुविधा प्रदान करेगी।

उद्योग/कंपनी के लिए:

भागीदारी के लिए मानदंड

49. प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना के लिए शीर्ष 500 कंपनियों को सूचीबद्ध करने के मानदंड क्या हैं?

मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के औसत सीएसआर व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान की है।

50. मेरी कंपनी 500 कंपनियों की प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं है। क्या हम फिर भी प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना में भाग ले सकते हैं?

हां, शुरुआती 500 कंपनियों में शामिल न होने वाली कंपनियां, बैंक या वित्तीय संस्थान भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। हालांकि, उन्हें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी, जो योजना में कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के आधार पर उनके समावेश का आकलन करेगा।

51. मेरी कंपनी सीधे इंटरनेशिप प्रदान नहीं कर सकती। मेरे पास और क्या विकल्प हैं?

यदि कोई कंपनी सीधे तौर पर इंटरनेशिप के अवसर प्रदान करने में असमर्थ है, तो वह निम्नलिखित के साथ गठजोड़ करके प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना में भाग ले सकती है:

- इसकी अग्रिम या पश्चवर्ती आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कम्पनियां (जैसे, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या विक्रेता)।
- इसके समूह के अंतर्गत अन्य कम्पनियाँ या संस्थाएँ।

इंटरनेशिप विवरण:

52. क्या इंटरनेशिप 12 महीने से अधिक बढ़ाई जा सकती है?

इंटरनेशिप की अवधि 12 महीने निर्धारित है। प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना के तहत इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

53. क्या कम्पनियों के लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है?

हां, कंपनियों के लिए इंटर्न को प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य वातावरण में व्यतीत हो, न कि प्रशिक्षण में।

54. क्या कम्पनियों को प्रशिक्षुओं को पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक नियुक्त करना अनिवार्य है?

हां, कंपनियों को प्रत्येक इंटर्न को जॉइन करने पर पर्यवेक्षक या सलाहकार नियुक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को प्रत्येक इंटर्न के सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को प्रदान करने या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

55. क्या प्रशिक्षु मौजूदा श्रम कानूनों के तहत कर्मचारी के रूप में योग्य हैं?

यह स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप की पेशकश मंत्रालय, या संबंधित कंपनी और चयनित इंटर्न के बीच नियोक्ता-कर्मचारी के किसी भी संविदात्मक या कानूनी सम्बन्ध को स्थापित नहीं करेगी। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि इंटर्नशिप की ऐसी पेशकश को न तो इंटर्नशिप की अवधि के दौरान या उसके बाद कंपनी या मंत्रालय द्वारा भविष्य में रोजगार की पेशकश या वादे की प्रकृति में माना जा सकता है। इसके अलावा, श्रम मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.09.2024 में स्पष्ट किया है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के प्रयोजन के लिए, इंटर्न को कर्मचारियों के समकक्ष नहीं माना जाएगा। उक्त कार्यालय ज्ञापन अनुलग्नक- 1 में संलग्न है।

इंटर्न को वित्तीय सहायता:

56. प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या होगा?

प्रशिक्षुओं को 12 महीने की पूरी इंटर्नशिप अवधि के दौरान ₹5,000 की मासिक सहायता मिलेगी। इस राशि में से:

- कंपनी इंटर्न की उपस्थिति, आचरण और संबंधित कंपनी नीतियों के आधार पर अपने सीएसआर फंड से हर महीने 500 रुपये जारी करेगी।
- इसके बाद सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए इंटर्न के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे 4,500 रुपये का भुगतान करेगी। कंपनी अपने स्वयं के फंड से अतिरिक्त मासिक सहायता प्रदान कर सकती है।

57. क्या कोई कंपनी इंटरन को मासिक सहायता के रूप में ₹500 से अधिक प्रदान कर सकती है?

हां, यदि कोई कंपनी मासिक सहायता के रूप में ₹500 से अधिक प्रदान करना चाहती है, तो वह सीएसआर फंड द्वारा कवर किए गए ₹500 के अतिरिक्त, अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है।

इंटरन के लिए बीमा कवरेज:

58. क्या कम्पनियां प्रशिक्षुओं को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं?

नहीं, कंपनियाँ इंटरन को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। प्रत्येक इंटरन को भारत सरकार की बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाएगा:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

इन बीमा योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। कंपनी प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने का विकल्प चुन सकती है।

59. कंपनियां इंटरनशिप के अवसर कैसे पोस्ट कर सकती हैं?

साझेदार कंपनियों को पोर्टल पर एक समर्पित डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा, जहां वे सीधे अपने इंटरनशिप अवसरों को पोस्ट कर सकते हैं।

इंटरनशिप पोस्टिंग:

60. इंटरनशिप पोस्टिंग में क्या जानकारी शामिल होनी चाहिए?

इंटरनशिप पोस्टिंग में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

- इंटरनशिप का स्थान
- इंटरनशिप की भूमिकाएं और कार्य
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक
- कंपनी द्वारा प्रदान की गई कोई भी सुविधा (जैसे, आवास, परिवहन, भोजन आदि)

61. क्या साझेदार कंपनियां अपने पोस्ट किए गए इंटरनशिप अवसरों को संपादित या हटा सकती हैं?

हां, अवसर की प्रारंभिक पोस्टिंग में किसी भी त्रुटि के मामले में भागीदार कंपनियों के पास इंटरनशिप अवसर को हटाने या संपादित करने का विकल्प होगा। हालांकि, यह

ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये परिवर्तन इंटरनेट शिप अवसर पोस्ट करने के लिए निर्दिष्ट विंडो के भीतर किए जाने चाहिए।

62. पोर्टल पर कंपनी द्वारा किस प्रकार की इंटरनेट शिप भूमिकाएं पोस्ट की जा सकती हैं?

कंपनी को उन इंटरनेट शिप भूमिकाओं को पोस्ट करना चाहिए जो इंटरनेट के कौशल विकास को प्रोत्साहित करें। कंपनियों को उन भूमिकाओं के लिए इंटरनेट शिप की पेशकश नहीं करनी चाहिए जिनमें कौशल शामिल नहीं है, जैसे सफाई, डिलीवरी, कुली, सुरक्षा गार्ड, या ऑफिस बॉय।

63. कंपनी किसी इंटरनेट की योजना में भागीदारी की पुष्टि कैसे करती है?

जब कोई इंटरनेट इंटरनेट शिप में शामिल हो जाता है, तो कंपनी को पोर्टल पर उनकी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।

64. क्या कंपनियों के पास इंटरनेट के दुर्व्यवहार/कम प्रदर्शन/अनुपस्थिति के मामलों से निपटने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है?

हां, प्रशिक्षुओं को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि किसी भी दुर्व्यवहार/दुर्व्यवहार/अनुपस्थिति के मामले में, कंपनी उनकी इंटरनेट शिप समाप्त कर सकती है। शिकायत निवारण तंत्र के एक भाग के रूप में, कंपनी से एक नोडल व्यक्ति को पीएम इंटरनेट शिप योजना पोर्टल के माध्यम से ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

65. क्या कम्पनियों को प्रशिक्षुओं की निगरानी और मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता होगी?

हां, कंपनियां इंटरनेट के प्रदर्शन का आकलन करने और उन्हें नियमित फीडबैक देने के लिए निगरानी और मूल्यांकन ढांचा तैयार कर सकती हैं। इस तंत्र का उपयोग इंटरनेट की भविष्य की रोजगार संभावनाओं पर निर्णय लेने के लिए भी किया जा सकता है।

66. इस योजना के लिए प्रशिक्षुओं की भर्ती के स्रोत क्या हैं?

कंपनी केवल निर्दिष्ट पोर्टल से ही इंटरनेट की भर्ती कर सकती है। कंपनी द्वारा निर्दिष्ट नौकरी विवरण से मेल खाने वाले संभावित उम्मीदवारों की सूची पोर्टल पर दिखाई देगी। पोर्टल का एल्गोरिदम उम्मीदवारों की संभावित सूची को दर्शाएगा, जो इंटरनेट शिप के अवसरों की संख्या से लगभग दोगुनी या तिगुनी होगी। कंपनियां पोर्टल से उम्मीदवारों का चयन करने में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती हैं।

67. क्या इंटरनेट शिप का प्रस्ताव नियोक्ता-कर्मचारी संबंध बनाता है?

नहीं, इंटरनेट शिप प्रस्ताव मंत्रालय, संबंधित कंपनी और चयनित इंटरनेट के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित नहीं करता है।

68. क्या इंटरनेट शिप प्रस्ताव को भविष्य में रोजगार का वादा माना जा सकता है?

नहीं, इंटरशिप प्रस्ताव को संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा इंटरशिप अवधि के दौरान या उसके बाद भविष्य में रोजगार देने के वादे के रूप में नहीं समझा जा सकता।

69. क्या प्रशिक्षुओं को संस्थान के नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है?

हां, प्रशिक्षुओं को संस्थान के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जिनमें समय, छुट्टियां, अवकाश, आचरण और अनुशासन से संबंधित नियम शामिल हैं।

प्रदर्शन की मान्यता:

70. कम्पनियां उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को कैसे मान्यता दे सकती हैं?

कम्पनियाँ उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को कई तरीकों से सम्मानित कर सकती हैं, जैसे:

- कंपनी की वेबसाइट या सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना।
- उन्हें कंपनी के समाचारपत्रों या सफलता की कहानियों में शामिल करना।
- पुरस्कार या प्रमाण पत्र प्रदान करना।
- आगे के विकास या उन्नति के अवसर प्रदान करना

71. मंत्रालय कम्पनियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर कैसे मान्यता देगा?

मंत्रालय असाधारण प्रदर्शन, नवाचार और अन्य मानदंडों के आधार पर कम्पनियों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करेगा।

इंटरशिप छोड़ने के मामले:

72. यदि कोई इंटरन इंटरशिप पूरी होने से पहले ही वापस ले लेता है या छोड़ देता है तो क्या होगा?

यदि कोई इंटरन वापस ले लेता है या काम छोड़ देता है, तो कंपनी को इंटरन को "ड्रॉपआउट" के रूप में चिह्नित करके पोर्टल के माध्यम से सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए। इससे उम्मीदवार को आगे भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

73. किसी इंटरन को ड्रॉपआउट मानने के सामान्य मानदंड क्या हैं?

किसी इंटरन को ड्रॉपआउट माना जा सकता है यदि वह:

- अचानक और बिना किसी सूचना के उनकी इंटरशिप आवश्यकताओं पर ध्यान देना बंद कर दें।
- अपने गुरु या पर्यवेक्षक द्वारा दो बार संवाद करने के प्रयास के बावजूद प्रतिक्रिया देने या पुनः शामिल होने में असफल होना।
- आगे जारी रखने की अनिच्छा व्यक्त करें।

इंटरनेट के तौर-तरीके:

74. क्या कंपनी के दिशानिर्देश प्रशिक्षुओं की छुट्टी नीति को नियंत्रित करेंगे?

हां, इंटरनेट के लिए छुट्टी नीति कंपनी के आंतरिक दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगी। इसमें बीमारी की छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी और अन्य प्रकार की छुट्टियों के लिए नीतियां शामिल हो सकती हैं।

75. क्या इंटरनेट अवकाश ले सकते हैं?

चिकित्सा आपातस्थिति या पारिवारिक आपातस्थिति जैसी असाधारण परिस्थितियों में, प्रशिक्षुओं को कंपनी की नीतियों और/या मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार दो महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है।

76. क्या अवकाश के दौरान प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता मिलेगी?

अवकाश अवधि के दौरान कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

77. यदि किसी इंटरनेट की अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो जाए तो क्या होगा?

यदि अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो जाती है, तो प्रशिक्षु को अपनी इंटरनेट बंद करनी होगी और अगले इंटरनेट प्रस्ताव चक्र में पुनः आवेदन करना होगा।

78. क्या कंपनियां आवास, परिवहन, कैटीन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं?

कंपनियों को इंटरनेट को आवास, परिवहन या कैटीन जैसी सुविधाएं प्रदान करने की बाध्यता नहीं है। हालांकि, अगर वे इसे आवश्यक या लाभकारी मानते हैं तो उनके पास ये सुविधाएं प्रदान करने की लचीलापन है।

समाप्ति का प्रमाणपत्र:

79. क्या कम्पनियों को प्रशिक्षुओं को कार्य समाप्ति का प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा?

हां, कंपनियों को इंटरनेट को पूरा होने का प्रमाण पत्र देना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाण पत्र केवल भागीदार कंपनी द्वारा ही वितरित किया जाए।

पोर्टल प्रश्न:

80. उद्योग/कंपनी की ओर से किस प्रकार के उपयोगकर्ताओं को पोर्टल तक पहुंचने की अनुमति है?

निम्नलिखित उपयोगकर्ता प्रकारों को पोर्टल तक पहुंच प्राप्त है:

- कंपनी व्यवस्थापक: कंपनी प्रोफ़ाइल स्थापित करने और कंपनी और नेटवर्क संस्थाओं के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और कंपनी की इंटरनेट योजना की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार।

- नोडल अधिकारी: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है, इंटरशिप योजना का प्रबंधन करता है, मानव संसाधन नियुक्त करता है, और शिकायतों का निपटारा करता है।
- मानव संसाधन: इंटरशिप पोस्टिंग का प्रबंधन, आवेदनों की देखरेख, तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति।
- पर्यवेक्षक/संरक्षक: प्रशिक्षुओं के लिए संपर्क बिंदु। प्रशिक्षुओं की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, सीखने और विकास तथा कार्यप्रवाह के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।

81. नोडल अधिकारी की भूमिका क्या है?

नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना से संबंधित सभी संचार के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। वे कंपनी की इंटरशिप योजना का प्रबंधन करते हैं, एचआर नियुक्त करते हैं, और शिकायतों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

82. एक मानव संसाधन विभाग को कितने प्रशिक्षु नियुक्त किये जा सकते हैं?

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) प्रत्येक 100 इंटरन के लिए 1 एचआर के अनुपात की सिफारिश करता है।

83. क्या नेटवर्क संस्थाएं मूल कंपनी की ओर से इंटरशिप पोस्ट कर सकती हैं?

नहीं, समूह की कंपनियाँ, सहायक कंपनियाँ, संबद्ध ठेकेदार, विक्रेता और वितरक मूल कंपनी की ओर से इंटरशिप पोस्ट नहीं कर सकते। वे केवल अपने संगठन के लिए ही इंटरशिप पोस्ट कर सकते हैं।

84. कंपनी प्रशासक उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को कैसे देख सकते हैं?

एडमिन उपयोगकर्ता किसी विशेष उम्मीदवार द्वारा मूल कंपनी या समूह इकाई के विरुद्ध सिस्टम में दर्ज शिकायतों की जांच कर सकता है।

85. क्या मानव संसाधन उपयोगकर्ता अपनी कंपनी के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की संख्या देख सकते हैं?

हां, एचआर उपयोगकर्ता अपनी कंपनी के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की संख्या देख सकते हैं।

No.S-65025/01/2024-SS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Social Security Division

Shram Shakti Bhawan, New Delhi
Dated 27th September, 2024

Office Memorandum

Subject:- Legal clarification for the PM Internship Scheme regarding applicability of Labour Laws on Interns-reg.

The undersigned is directed to refer to Ministry of Corporate Affairs' communication No. F. No. CSR-13/29/2024 dated 18.09.2024 on the above mentioned subject and to state that the issue has been examined in the light of provisions of EPF & MP Act, 1952, in consultation with EPFO.

2 It is stated that EPF contribution is payable in respect of employees employed for wages in accordance with the terms of the contract employment (section 2(f) and 2(b) of the Act). The Payment of Wages Act 1936 also, states that wages are paid in accordance with terms of employment, express or implied.

“Thus, the terms of engagement of a person with an establishment is the crucial determinant whether the amount being paid will qualify as wages or not.”

3. Reference is also invited to M/o Corporate Affairs' letter dated 18.09.2024 wherein it has been stated as *“The internship would not entail employment for wages in any kind of work. Further, the internship allowance of Rs 4500 is to be paid by the Government of India directly to the account of the intern”*.

4. In view of the aforesaid provisions and above observation of M/o Corporate Affairs, for the purpose the PM Internship Scheme (PMIS), *prima-facie* interns do not qualify as employees.

This issues with the approval of Competent Authority.



(Sudesh Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India
e-mail : sudesh.kumar73@nic.in
Tel. No. 011-23473009

To

Ministry of Corporate Affairs
(Ms Himani Sharma, Assistant Director)
Himani.sharma25@gov.in
5th Floor, A Wing, Shastri Bhawan, Dr RP Road, New Delhi.